

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2014 — फाल्गुन 7, शक 1935

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

“ नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-230/गृह-सी/2006. — यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये.

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा-4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 26 फरवरी, 2014 से 03 माह तक निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, अर्थात् :-

“विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा ट्रेडिंग के लिए बोर्ड, जिसमें इसके उत्तरवर्ती शामिल हैं, द्वारा नियुक्त सभी वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यकारी (आपरेटिव) को सम्मिलित करते हुए कार्यपालक तथा सभी कार्मिक (जिसमें अधिकारी, कर्मचारी एवं लिपिक वर्गीय कार्मिक सम्मिलित हैं).”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 4/230/गृह-सी/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-230/गृह-सी/2006, दिनांक 26 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th February 2013

#### NOTIFICATION

No. F 4-230/Home-C/2006. — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified below ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work in the following essential services with effect from 26 February, 2014 for 03 Months, namely :-

“All Scientific, technical, executive including operative and all personnel (which includes officers, employees and ministerial personnel) appointed by the Board including its successors for Electricity generation, transmission, distribution and Trading.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.